नयी जनसंख्या नीति में कमजोर वर्ग का ध्यान रखना जरूरी: आलोक रंजन
UP health budget up by 11% this year

LUCKNOW: A two-day state consultation on review of Uttar Pradesh Population Policy began here on Friday.

Delivering the keynote address, chief secretary Alok Ranjan said the state government had given the health sector priority and new policies were being introduced for the people. He said UP's growth rate did not get projected well despite so much having been done.

"The health budget this year is 11% more than the previous year and the state has succeeded to reduce the IMR to 50," the chief secretary said, adding that health models of Kerala, Bangladesh or Nepal could be studied, as their health indicators were better.

Keshav Desiraju, secretary (pd) in union government, said efforts should be made to give people an environment where improvement in health facilities start from home.

UP adopted the state population policy in July 2000, which is applicable till 2016. The policy is aimed at reaching the replacement level fertility of 2.1 by 2016 for attaining population stabilization.
‘नई जनसंख्या नीति के लिए ठोस सुझाव जरूरी’

लखनऊ (उपो.) मुख्य सचिव आलोक राजने कहा कि वर्तमान जनसंख्या नीति को समन्वय करने हेतु भविष्य की जनसंख्या नीति के लिए ठोस सुझाव आवश्यक रहेगी। संसाधित जनसंख्या नीति में समय के हालांकि पर रहने वाले और कामकाजी व्यवस्थाएँ की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की स्थिति में रखना जरूरी है, जिससे वे अपने सर्वोग नव लाना कर सकें।

राजने ने बताया कि अगले दिन नई नीति की बारात करने के लिए भविष्य की नीति के लिए संभवतः बारेंदो सदस्यों की अधिकारी केबीएस डी वोल्ड के अध्यक्ष की हुज्जा गया। साथ ही साथ, नई नीति को निर्देशित करने का सार्वजनिक कार्य किया जाएगा।

राजने ने बताया कि नई नीति की बारात करने के लिए संभवतः बारेंदो सदस्यों की अधिकारी केबीएस डी वोल्ड के अध्यक्ष की हुज्जा गया। साथ ही साथ, नई नीति को निर्देशित करने का सार्वजनिक कार्य किया जाएगा।
नई जनसंख्या नीति में लक्ष्य पूरे करने का संकल्प

कार्यशाला

लखनऊ के समाज सेवक सशक्तिकरण संगठन की गणना के आधार पर नई जनसंख्या नीति 2016 की स्थापना होती है। नीति के अंतर्गत सभी जनसंख्या नीति अनुसार, प्राथमिक स्तर की सेवाएं निःसंदर्भ रूप से की जाएँगी।

लखनऊ के समाज सेवक सशक्तिकरण संगठन की गणना के आधार पर नई जनसंख्या नीति 2016 की स्थापना होती है। नीति के अंतर्गत सभी जनसंख्या नीति अनुसार, प्राथमिक स्तर की सेवाएं निःसंदर्भ रूप से की जाएँगी।
बड़ती जनसंख्या के कारण नहीं दिखती प्रगति: रंजन

राज्य मुख्यमंत्री रंजन सचिव आर्य के रंजन ने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहां की प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है। बड़ती जनसंख्या प्रदेश की आर्थिक प्रगति से दूर थानास्थल लोगों पर भी डाला रहा है। उन्होंने माना है कि प्रदेश में हिंदू और मूर्त दोनों में काफी कमी आई है। बालिकाओं के हाथ अभी भी बढ़ती आसकत से पीछे है। शिक्षा तथा दूर का रािशीय उत्सव 40 है, जबकि प्रदेश में यह घटकर 50 आ गई है। इसे और कर दे करने के प्रमाण जाता है। रंजन सचिव आर्य के रंजन उपर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 के वर्तमान स्थिति और भविष्य के नए अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्यराजशीर्ष कार्यक्रम का सुपरिस्थत कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने दूर का रािशीय उत्सव के लिए 1300 करोड़ का बजट का प्रस्तावन किया है।
हां, पूरे हए सेहत के सपने, अब नई जनसंख्या नीति

राज्य बुधवार, समाचार : नयाम नीतियों व स्थितियों के आवश्यक बन के सेहत के सपने पूरे हए हुए हैं। अब सरकार सभी को बोकार नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। राज्य सरकार के एक पार्षद नितिता शेषन ने राज्य के पुराने स्थानीय परिषदें के लिए नयाम नीति लाने के लिए भावना सरकार के पूरे सत्यश निवास बदले देशसेवा को प्रायोगिक नयाम नितिता नियोजक समीन्द्र के सामने की गई है।

नयाम नीति ने कहा कि स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के लिए नयाम नीति का बदले देशसेवा की गई है। सरकार नयाम नीति विकसित करना चाहती है, जिसे पूरे देश 'वड्डा' करे। इसी प्रणा से नयाम नीति स्थानीय बनने का फैसला हुआ है। उन्होंने बता कि स्थानीय क्षेत्र में सभी समुदायीय संस्थाओं के लिए इन्हें अधिकारों व प्रावधानों की उपलब्धता करके एक प्रभुत्व निर्माण होगा।

सीएफएसए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विकास नीति में समूहीय नीति की स्थानीय नीति के लिए भावना सरकार के पूरे सत्यश निवास बदले देशसेवा को प्रायोगिक नयाम नितिता नियोजक समीन्द्र के सामने की गई है।

प्रदेश भर से आए सुझाव

- सुझाव देते हैं: सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति लाने का प्रयास जारी हैं।
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम
- सभी संस्थाओं में स्थानीय नीति के लिए आवश्यक विनियम